RAJYA SABHA

Wednesday, the 9th May, 1962/the 19th *Vaisakha,* 1884 (Safca)

The House met at eleven of the clock, MR. CHAIRMAN in the Chair.

ORAL ANSWERS TO QUESTIONS

पंचायतों को राजस्व का आवंटन

*३३८. **श्री भगवत नारायण भार्गव :** क्या सामुदायिक विकास, पंचायती राज और सहकार मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि उड़ीसा राज्य के अतिरिक्त क्या किन्ही और राज्य सरकारों ने अपने राजस्व (भू-राजस्व छोड़कर) का कोई भाग पंचायतों को दिया है ?

ALLOCATION OF REVENUES TO PANCHAYATS

*338. SHRI B. N. BHARGAVA: Will the Minister of COMMUNITY DEVELOPMENT, PANCHAYATI RAJ AND COOPERATION be pleased to state whether any State Governments other than that of Orissa have allocated any part of their revenue (except land revenue) to the Panchayats]

सामुदायिक विकास, पंचायती राज और सहकार मंत्रालय में उपमंत्री (श्री एस० डी० मिश्र) : जी, किसी ने नहीं । श्रीमान जी, मैं एक बात और कह दूं । भूमि लगान को कुछ अन्य सरकारों की तरह उड़ीसा सरकार ने पंचायतों के लिये कोई हिस्सा नहीं दिया है, लेकिन केंदू पत्ती (बीड़ी पत्ती) के बेचने से जो मुनाफा होता है उसका पचास प्रतिशत पंचायती राज संस्थाओं को दिया जाता है ।

t[THE DEPUTY MINISTER IN THE MINISTRY OF COMMUNITY DEVELOPMENT, PANCHAYATI RAJ AND COOPERATION (SHRI S. D. MISRA) : None, Sir.

t[ ] English translation. 233

I may add, Sir, that Orissa Government unlike some other State Governments has not made any allocation from the land revenue. But it has allowed 50% of the profits from the sale of Kendu leaves (Bidi leaves) to the Panchayati Raj institutions.]

श्री भगवत नारायण भार्गव : क्या मैं यह जान सकता हूं कि किन किन राज्यों ने अपनी मालगुजारी का कितना प्रतिशत पंचायती राज को दिया है ?

श्री एस० डी० मिश्र : श्रीमान् जी, इस सम्बन्ध में अनेक राज्यों ने अनेक तरह से बटवारा किया है जो निम्न प्रकार से है :—

आंध्र	.	२५ नया पैसा प्रति व्यक्ति ।
आसाम	.	१५ प्रतिशत ।
बिहार	.	६ १/४ प्रतिशत ।
केरल	.	कुछ नहीं दिया है ।
उड़ीसा	.	कुछ नहीं दिया है ।
मैसूर	.	३५ प्रतिशत ।
उत्तर प्रदेश	.	६ १/४ प्रतिशत ।

कुछ ऐसे राज्य और हैं जिन्होंने कुछ नहीं दिया है ।

श्री भगवत नारायण भार्गव : क्या केन्द्रीय सरकार ने इस सम्बन्ध में अपनी नीति निर्धारित करके राज्य सरकारों को सुझाव दिया है या वे स्वयं अपनी इच्छा से दे रही हैं ?

श्री एस० डी० मिश्र : केन्द्रीय सरकार की राय है कि पंचायतों को धनराशि मिलनी चाहिये और इसके सम्बन्ध में अभी एक कमेटी बनाई जाने वाली है जो राज्य सरकारों से मशवरा करके इस बारे में निर्णय करेगी कि कितना प्रतिशत पंचायत विभाग को मिलना चाहिये ।

श्री देवकी नन्दन नारायण : अभी आपने सब स्टेटों के बारे में बतलाया कि वे पंचायती विभाग को कितना देते हैं लेकिन महाराष्ट्र के बारे में आपने कुछ नहीं बतलाया। कृपया महाराष्ट्र के बारे में बतलायें कि वहां पंचायती राज्य को लैंड रेवेन्यू से कितनी धनराशि मिलती है ?

श्री एस० डी० मिश्र : वहां २५ से ३० प्रतिशत तक मिलता है ।

SHRI DEOKINANDAN NARAYAN: It is 100 per cent.

श्री एस० डी० मिश्र : गुजरात १०० प्रतिशत देता है ।

SHRI DEOKINANDAN NARAYAN: I would like to tell the hon. Minister that it is 100 per cent., 25 per cent, for Gram Panchayats and 75 per cent. for Zila Parishads.

श्री एस० डी० मिश्र : मैंने बतलाया कि २५ से ३० प्रतिशत तक देते हैं। गुजरात १०० प्रतिशत देता है ।

SHRI SATYACHARAN: May I know whether the Planning Commission has suggested any uniform scheme in the matter of allocation of funds to the States with regard to Panchayati Raj?

SHRI S. D. MISRA: I have already replied and I have already stated that this matter is under the active consideration of the Government of India and the Committee for Resources is to be set up, which will go round the States and find out the position and make its own recommendations.

SHRI N. B. MAITI: May I know, Sir, the allotment made by the West Bengal Government from its land revenue or other revenue for the purpose of development of Panchayati Raj?

SHRI S. D. MISRA: Sir, as far as allotment from land revenue is concerned, I have stated that the West Bengal Government does not give any land revenue to the Panchayati Raj institutions. But it is giving a certain part of some other things, cess, etc. and it is making contributions from its other revenues.

टेलीफोन को ट्रंक कालों का आधुनिकीकरण

*३३९. **श्री नवाबसिंह चौहान** : क्या **परिवहन तथा संचार** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि टेलीफोन की ट्रंक कालों की दरों का आधुनिकीकरण किया जा रहा है ; और

(ख) यदि हां, तो यह आधुनिकीकरण किस प्रकार किया जा रहा है और नई व्यवस्था के क्या लाभ हैं ?

t[RATIONALISATION OF TRUNK TELEPHONE CALLS

*339. SHRI NAWAB SINGH CHAUHAN: Will the Minister of TRANSPORT AND COMMUNICATIONS be pleased to state:

(a) whether it is a fact that the charges for trunk telephone calls are being rationalised; and

(b) if so, in what manner they are being rationalised and what are the advantages of the new arrangement?]

परिवहन तथा संचार मंत्री (श्री जगजीवन राम) : (क) ट्रंक काल शुल्क की दरों को जितने भागों में बांटा गया है उनकी संख्या कम करने के प्रस्ताव पर तेजी से विचार किया जा रहा है ।

(ख) प्रश्न ही नहीं उठता ।

†[ ] English translation.